जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 19 संख्याः 164 प्रभात जालोर, गुरुवार 19 सितम्बर, 2024 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

''वन नेशन, एक इलैक्शन'' के नारे से भाजपा देश का राजनीतिक एजेण्डा पुनः निर्धारित करना चाहती है

2014 से यह एजेण्डा मोदी ही तय करते आये थे, पर इस बार राहुल गांधी के ''कास्ट सैंसस (जातजन गणना) के नारे ने देश का राजनीतिक एजेण्डा निर्धारित करने का अधिकार छीन लिया था

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा मौजूदा चुनौतियों का सामना किये जाने के दौरान ही, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ''वन नेशन वन इलैक्शन'' (ओ.एन.ओ.ई.) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विपक्ष ने इसे ''ध्यान बाँटने वाली'' ''चाल'' की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2014 से ही इस विचार की जोरदार वकालत करते आ रहे हैं। उन्होंने इस साल लाल किले से किये गये स्वतंत्रता दिवस के अपने सम्बोधन में भी इस मुद्दे का प्रमुखता से उल्लेख किया था। विडम्बना देखिये कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र एवं झारखंड को छोड़ते हुये, केवल हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में ही चुनाव कराने का निर्णय लिया है। इन चारों राज्यों के विधानसभा चुनाव बड़ी आसानी से एक साथ हो सकते थे।

- चुनाव विशेषज्ञों का मानना है, कि, हालांकि ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' स्थापित करने में बहुत समय और बहुत श्रम लगेगा।
- सम्भवतः शायद आज इसे लागू भी नहीं कर पायें, और इस मुद्दे पर यूटर्न भी कर लें।
- पर जब तक फाइनल निर्णय नहीं होता, इस नारे पर बहस तो शुरू हो गयी है, और जारी रहेगी।
- भाजपा के नीतिकारों का मानना है, यह बहस राहुल के ''कास्ट सैंसस'' का सही जवाब है।
- सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सर्वे के अनुसार अस्सी प्रतिशत जनता ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' के पक्ष में है। केवल कुछ नेता, विशेषकर क्षेत्रीय नेता ''एक राष्ट्र, एक चुनाव'' की व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्योंकि, इस व्यवस्था से उनका क्षेत्रीय प्रभाव ढह सकता है।

आई.टी. एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रस्ताव की क्रियान्विति सरकार के इस कार्यकाल में ही हो जायेगी तता 2029 में सभी चुनाव एक साथ सम्पन्न होंगे। लेकिन यह विचार अनेक कारणों से बेतुका प्रतीत होता है, जिनमें से प्रमुख कारण है- विपक्ष शासित राज्य सरकारों के साथ सर्वसम्मति बनाने की चुनौतियाँ।

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू द्वारा मन्त्रिमंडल के इस निर्णय कर दिये जाने के बाद, सरकार को संसद के शीतकालीन सत्र मे एक विधेयक पेश करना होगा। इसके साथ ही, इस प्रस्ताव की क्रियान्विती के लिये आवश्यक विधायी परिवर्तन लाने के लिए सम्बन्धित विधेयक भी पेश करने होंगे। इसके बाद, कम से कम 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा इस प्रस्ताव का पास किया जाना अनिवार्य होगा। मुद्दे की बात यह है कि इस प्रस्ताव की क्रियान्विती में आने वाली चुनौतियां बहुत जटिल होंगी तथा भविष्य में, एक स्थिति पर पहुँचकर, सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे हटा लेने की

(शेष पृष्ठ 3 पर)

आतिशी शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। आम आदमी पार्टी (आप) की जानी-मानी नेता तथा दिल्ली सरकार की मन्त्री आतिशी शनिवार, 21 सितम्बर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। इससे पार्टी के अन्दर उनकी स्थिति और मजबूर होगी।

दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना ने मनोनीत मुख्यमंत्री के लिए आतिशी की शपथ के लिये 21 सितम्बर की तिथि प्रस्तावित की है।

- दिल्ली के राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शपथ ग्रहण के लिए शनिवार 21 सितम्बर की तारीख प्रस्तावित की है।

ज्ञातव्य है कि अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल का त्याग पत्र राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के पास भेज दिया गया है। लेकिन आप विधायक दल ने अभी तक शपथ-ग्रहण समारोह की तिथि की पुष्टि नहीं की है।

आतिशी, जो सर्वसम्मति से आप विधायक दल की नेता चुन ली गई थीं, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने के लिये पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने पार्टी का नेतृत्व उस समय ग्रहण किया,

(शेष पृष्ठ 3 पर)

देश की जी.डी.पी. में कर्नाटक का योगदान 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 8.2 प्रतिशत हुआ

प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी कर्नाटक देश भर में तीसरे स्थान पर

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। कर्नाटक में इकॉनमिस्ट तथा बिज़नेस प्रोफैशनल आर्थिक उदारीकरण को धन्यवाद देते हैं, जिसने, देश में नई आर्थिक नीति अपनाने से पहले की तुलना में ग्रोथ को लगभग दोगुना कर दिया है और जिसने देशभर में उद्यम को बढ़ावा दिया है। आज, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइज़री काउन्सिल भी इस तथ्य को स्वीकार करती है और उनका कहना है कि 1960-61 में देश की जी.डी.पी. में कर्नाटक का जो शेयर 5.4 प्रतिशत था वो 1990-91 तक लगभग यही बना रहा। लेकिन, उदारीकरण के बाद, कर्नाटक में तेजी से ग्रोथ हुई और 2000-01 तक उसका जी.डी.पी. शेयर बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गया। इसके बाद 2023-24 मे कर्नाटक का जी.डी.पी. शेयर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया तथा कर्नाटक देश के सर्वोच्च पांच राज्यों में शामिल हो गया।

- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट ने माना है कि कर्नाटक व अन्य दक्षिणी राज्यों के विकास का श्रेय नरसिम्हाराव की सरकार में तत्कालीन वित्तमंत्री मनमोहन सिंह के मार्गदर्शन में हुए आर्थिक उदारीकरण को जाता है।
- 1960-61 से 1990-91 तक कर्नाटक का योगदान लगभग 5.4 प्रतिशत था, जो आर्थिक उदारीकरण के बाद बढ़ कर 6.2 प्रतिशत हो गया था और अब 8.2 प्रतिशत हो गया है।
- यही वजह है कि कर्नाटक आई.टी. सैक्टर में नम्बर वन बना और अब स्पेस टैक्नॉलजी सैक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रवासी लोग कर्नाटक जैसे शान्तिप्रिय राज्य में भी हाल ही में हिन्दी को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश भले ही कर रहे हों, जबकि कर्नाटक भाषाई कट्टरता तथा भाषाई आन्दोलनों को हवा देने के मामले में कभी आगे नहीं आया है। लेकिन यह भी सत्य है कि अंग्रेजी भाषा से राज्य की इंजीनियरिंग तथा कम्प्यूटर की हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर कुशलता को बल मिला है तथा इस भाषा की बदौलत, इस राज्य को देश के ''सिलिकॉन वैली'' के रूप में उभरने में मदद मिली है तथा भारत को आउटसोर्सिंग से मिलने वाले काम का भी काफी लाभ मिला है।

प्रधानमंत्री की ''इकॉनॉमिक एडवाइज़री कमेटी (ई.ए.सी.) द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट ''रिलेटिव इकॉनॉमिक परफोर्मेंस ऑफ इन्डियन स्टे्टस :

(शेष पृष्ठ 3 पर)

कांग्रेस ने किए हरियाणा में सात चुनावी वादे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव का 53 पृष्ठीय घोषणापत्र जारी किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तथा अन्य पार्टी नेताओं ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए सात चुनावी वादों की घोषणा की। इनमें प्रमुख हैं- 18 से 60 वर्ष के बीच सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपए की राशि देकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण तथा इससे ऊपर की आयु वाली महिलाओं को 2000 रु. की पैंशन व सभी महिलाओं को 500 रु. में गैस सिलैण्डर दिया जाना।

इन नेताओं ने रिटायर हो चुके सरकारी कर्मचारियों को 6000 रु. प्रतिमाह पैंशन देने की घोषणा भी की।

कांग्रेस ने वादा किया कि वो दो लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेगी तथा हरियाणा को शराब मुक्त बनाएगी।

इनके अलावा कांग्रेस ने सभी को 25 लाख रु. तक का मुफ्त इलाज, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सौ गज के प्लॉट पर 3.50 लाख की लागत वाला दो कमरों का फ्लैट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एम.एस.पी.) की कानूनी गारंटी, जातियों का सर्वे तथा क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रु. करने का वादा किया है।

- कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2 हजार रु. तथा उससे अधिक उम्र की महिलाओं को 2000 रु. मासिक पेंशन देने व सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलैण्डर देने की घोषणा की।
- पार्टी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने व 6 हजार रु. पेंशन देने की घोषणा की और 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का वादा किया।
- पार्टी ने 25 लाख रु. तक का मुफ्त इलाज, 300 युनिट मुफ्त बिजली और गरीबों को 100 गज का 2 कमरों का फ्लैट देने का वादा भी किया।

खड़गे ने कहा, सात चुनावी वादों के अलावा कांग्रेस ने अपने 53 पृष्ठ के घोषणा पत्र में और बहुत से, वादे किए हैं। उन्होंने कहा, मोदी सरकार रसोई गैस के दाम बढ़ाती रहती है, जबकि, कांग्रेस का लक्ष्य इन्हें घटाने का है। उन्होंने सौ गज के प्लॉट पर दो कमरों का फ्लैट देने की बात पर जोर दिया। उन्होंने सभी चुनावी वादे पूरे करने का आश्वासन दिया।

''एक राष्ट्र एक चुनाव'' को मंत्रिमंडल की मंजूरी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली कमेटी ने देश भर के चुनाव दो चरणों में कराने का सुझाव दिया है।

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय कमेटी की इस संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट स्वीकार कर ली है रिपोर्ट में दो चरणों में देशभर के सभी चुनाव करवाए जाने का सुझाव दिया गया है।

कमेटी का सुझाव है कि पहले चरण में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव करवाए जाएं तथा दूसरे चरण में स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए जाएं। पहले चरण के 100 दिन बाद दूसरा चरण आयोजित हो। कमेटी ने इस

(शेष पृष्ठ 3 पर)

उपमुख्यमंत्री बैरवा को जिला रिव्यू कमेटी से हटाया

दूदू का जिला दर्जा जाने की चर्चायें उठीं

जयपुर, 18 सितम्बर। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के समय बने 17 नए जिलों के रिव्यू को लेकर बनाई गई कमेटी के संयोजक पद से सरकार ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को हटा दिया है। उनकी जगह कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को कैबिनेट सब-कमेटी का संयोजक बनाया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब दूदू से जिले का दर्जा जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ज्ञातव्य है कि दूदू को जिला बनाने के साथ ही इसका विरोध शुरू हो गया था। सत्रह नए जिलों में क्षेत्रफल के लिहाज से भी दूदू सबसे छोटा जिला है।

उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा से चुनकर आते हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार, बैरवा के कमेटी संयोजक रहते हुए अगर दूदू को लेकर कोई फैसला होता तो राजनीतिक लिहाज से जनता में गलत मैसेज जाता। संभवतः इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने यह फैसला लिया है।

सचिवालय में मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई। बैठक में पंवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद मदन दिलावर ने कहा कि हम पंवार कमेटी की रिपोर्ट को बारीकी से देख और समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने में जो मापदंड तय किए गए थे, उनके साथ कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं।

- मंत्री मदन दिलावर को नये जिलों के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है।
- बैरवा के संयोजक रहते दूदू का दर्जा छिनने से राजनीतिक समस्या खड़ी होने का अंदेशा था।

बैठक के बाद मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि नए चेयरमैन मदन दिलावर ने पूरी समीक्षा की। हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ बिंदुओं पर पंवार कमेटी से राय मांगी गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दरअसल, सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी के सहयोग के लिए रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है।

भजनलाल सरकार ने 17 नए जिलों और 3 संभागों के रिव्यू के लिए 12 जून को उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की थी। जिसमें उद्योग मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया था। कमेटी के मौजूदा सदस्यों को बरकरार रखा गया है।

गहलोत राज में बने जिलों को लेकर ललित के पंवार कमेटी ने सभी जिलों का दौरा करके रिपोर्ट लेने के साथ लोगों से मुलाकात की थी। कमेटी से 45 विधायकों, 5 सांसदों, 12 जिला प्रमुखों, 25 प्रधानों सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात करके अपने सुझाव और मांगें रखीं। भाजपा विधायकों ने गहलोत राज के कई छोटे जिलों की बाउण्ड्री पर आपत्ति जताते हुए नए इलाके जोड़ने और हटाने पर भी सुझाव दिया है।

जलेब चौक पर कब्जे को लेकर पूर्व राजपरिवार का दावा खारिज

जयपुर, 18 सितंबर। अपर सिविल न्यायालय उत्तर, महानगर द्वितीय ने जलेब चौक की खाली जमीन पर कब्जे से बेदखल करने से जुड़े मामले में पूर्व राजपरिवार से जुड़ा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूज़ियम ट्रस्ट का तीस साल पुराना दावा खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि कोवनांट की शर्त के अनुसार, जब जलेब चौक के रखरखाव का अधिकार ट्रस्ट को नहीं था तो उसने किस कानूनी अधिकार के इस संपत्ति को लाइसैंसधारियों को लाइसैंस पर दे दिया।

दावे में कहा गया कि जयपुर रियासत के पूर्व शासक स्वर्गीय महाराजा सवाई मानसिंह बहादुर ने अपने

- सवाई मानसिंह म्यूज़ियम ट्रस्ट ने 30 साल पहले जलेब चौक की खाली जमीन पर कब्जे के सम्बंध में दावा पेश किया था।

जीवनकाल में इस ट्रस्ट का वर्ष 1959 में गठन किया था। वहीं वर्ष 1972 में ट्रस्ट के चेयरमैन सवाई भवानी सिंह ने इस ट्रस्ट को संपत्तियां दी थीं। जलेब चौक की खाली जमीन पर ट्रस्ट ने लाइसैंस पद्धति पर आवेदकों को जगह दे रखी है, जहां आवेदक थड़ी और टीनशेड लगाकर रोजगार कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी 28 जून, 1994 को इन दुकानदारों के पास आए और उन्हें परिसर से हटाने और सामान जब्त करने की बात कही। अगले दिन निगम ने आकर थड़ियों और टीन शेड को हटाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर ट्रस्ट ने अपने

(शेष पृष्ठ 3 पर)

जोधपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म

जोधपुर, 18 सितम्बर (कासं)। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग को 8 साल की मासूम से रेप के आरोप में पुलिस ने डिटेन किया है। घटना के तीन दिन बाद तक परिवार ने डर के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए मां ने हिम्मत कर मामला दर्ज करवाया। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है।

लूणी थानाधिकारी हुकमसिंह ने

- पुलिस ने रेप के आरोप में 11 साल के बच्चे को डिटेन किया है।

बताया कि थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने मंगलवार को नाबालिग बेटी से रेप का मामला दर्ज करवाया है। सिंह ने बताया कि 14 सितंबर को मासूम के साथ पड़ोस में रहने वाले एक 11 साल के बच्चे ने रेप किया। शाम को बेटी की तबीयत खराब होने पर परिवार के लोगों को इसके बारे में पता चला।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

1960-61 में बंगाल का इकोनॉमिक योगदान जी.डी.पी. का 10.5 प्रतिशत था, पर अब घट कर 5.6 प्रतिशत रह गया है

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने प्र.मंत्री. के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, और तमिलनाडु जो 60 के तक भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केन्द्र थे, ने 1960-61 के बाद से अलग-अलग दिशाएं अख्तियार कर ली जिससे देश के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विभिन्नताएं उजागर होती है।

इकोनॉमिक एडवायज़री काउन्सिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर (ई.ए.सी.-पी.एम.) की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से ममता बनर्जी के शासन काल के बाद से देश की अर्थव्यवस्था में बंगाल के योगदान में भारी कमी आई है। इसके विपरीत महाराष्ट्र ने इस अवधि मे सतत ग्रोथ कायम रखी है। तमिलनाडु ने शुरूआती कमी के बाद शानदार सुधार किया और 1991 में भारत के उदारीकरण के बाद से भारी गति पकड़ी।

ई.ए.सी.-पी.एम. पेपर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान और प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन की तुलना की गई है। गत दशक में महाराष्ट्र के योगदान के मामूली सी कमी हुई है पर उसने 1960-61 से लेकर 2023-24 तक अपने आर्थिक प्रदर्शन को कायम रखा है।

इसके विपरीत पश्चिम बंगाल का आर्थिक योगदान लगातार घटा है। पश्चिम बंगाल 1960-61 में 10.5 प्रतिशत के साथ देश की जी.डी.पी. में योगदान ने तीसरे नम्बर पर था। यह 2023-24 में इसका योगदान घटकर 5.6 प्रतिशत रह गया है। यहां तक कि 2010-11 जब ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी तब भी राज्य का योगदान 6.7 प्रतिशत था।

- इसी रिपोर्ट के अनुसार, 1960-61 में बंगाल का जी.डी.पी. राष्ट्रीय औसत का 127.5 प्रतिशत था, जो अब राष्ट्रीय औसत जी.डी.पी का केवल 83.7 प्रतिशत ही है, राजस्थान व उड़ीसा से भी कम।
- 1960 के दशक में महाराष्ट्र, बंगाल व तमिलनाडू बड़े महारथी माने जाते थे, आर्थिक योगदान की दृष्टि से। महाराष्ट्र व तमिलनाडू ने तो अपनी पोज़ीशन लगभग बरकरार रखी है, पर बंगाल लगातार लुढ़कता ही चला गया।
- 1991 में देश ने जबसे इकोनॉमिक लिब्रलाइज़ेशन (आर्थिक उदारीकरण) का रास्ता पकड़ा, कर्नाटक आंध्र, तेलंगाना ने स्थिर गति से इकोनॉमिक समृद्धि बढ़ायी है।
- उत्तर भारत में दिल्ली व हरियाणा ने भी प्र.मंत्री की इकोनॉमिक सलाहकार मामलों की समिति की इस रिपोर्ट के अनुसार, छलांगें लगाई हैं इकॉनमी की दृष्टि से।

प्रतिव्यक्ति आय में भी पश्चिम बंगाल पिछड़ गया है। प्रतिव्यक्ति आय जो 1960-61 के दशक में 127.5 प्रतिशत थी, वह घटकर राष्ट्रीय औसत का 83.7 प्रतिशत रह गई है। पश्चिम बंगाल राजस्थान एवं ओडिशा जैसे राज्यों से भी पिछड़ गया है। प्रतिव्यक्ति आय में कमी से पता लगता है कि बंगाल राष्ट्रीय इकोनॉमिक ग्रोथ से तालमेल करने में जूझ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि यह सतत औद्योगिक भारत के पूर्वी भाग में विकास की कमी पर चिंता दर्शाती है।

महाराष्ट्र कई दशकों से अच्छी आर्थिक व्यवस्था के कारण देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान कर रहा है। हालांकि गत दशक में इसके योगदान में मामूली कमी देखी गई थी इसी बीच तमिलनाडु ने शुरुआत की कमी के बाद 1991 के बाद से अच्छी गति पकड़ी पेपर में इसके लिए आर्थिक सुधारों व उदारीकरण को क्रेडिट दिया जिसकी वजह से दक्षिणी राज्यों के

(शेष पृष्ठ 3 पर)